Regarding reported loss of lives and property due to landslides and floods in various parts of the country

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance, and I request that he may make a statement thereon:

?Loss of lives and property due to landslides and floods in various parts of the country.?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): अध्यक्ष महोदय, देश में बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं पर जो एहतियात बरते जाते हैं और उनके प्रबंधन के लिए सरकार की जो योजनाएं हैं, उसके सम्बन्ध में मैं बताऊंगा । माननीय मंत्री महोदय ने वायनाड के विषय में चर्चा की । खासकर, उस विषय में कल मेरा स्टेटमेंट टेबल पर प्रस्तुत भी हुआ था और उसके विषय में मैं बयान दे चुका हूं । लेकिन, फिर भी अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं इसके सम्बन्ध में अपडेट्स की कॉपी टेबल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, अभी जो विषय कॉलिंग अटेंशन का आया है, उसके संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि एन.डी.एम.ए. ने विभिन्न विषयगत और क्रॉस-कटिंग मुद्दों पर जोखिम विशिष्ट आपदाओं के प्रबंधन के लिए 33 दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें बाढ़ और भूस्खलन की आपदाएं भी शामिल हैं । राज्य सरकार इन दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुकूल तैयारी कर सकती है ।

राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेन्टर द्वारा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा, असम और उत्तर प्रदेश जैसे अधिक बाढ़ संवेदनशील राज्यों के लिए और जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे तुलनात्मक रूप से कम बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए बाढ़ जोखिम एटलस विकसित किया गया है ।

महोदय, भारत मौसम विज्ञान विभाग सभी प्रभावित/संभावित प्रभावित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए बाढ़ सहित नियमित और सटीक मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी बुलेटिन जारी करता है । आई.एम.डी. मौसम का महीनेवार और तीन दिन पूर्व अनुमान जारी करता था । अब तीन दिन पूर्व अनुमान को बढ़ाकर सात दिन का कर दिया गया है । केन्द्रीय जल आयोग भी नदियों के जलस्तर एवं बाढ़ का सात दिन का पूर्वानुमान सभी राज्यों को प्रतिदिन जारी करता है ।

महोदय, भारत सरकार द्वारा विभिन्न एजेंसियों के पूर्व अनुमान को जनता को तुरन्त उपलब्ध कराने के लिए 354 करोड़ रुपये के कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल योजना लागू की है, जिसके जरिए आपदा से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों को एस.एम.एस. के जरिए सूचना तुरन्त जारी की जाती है । पिछले दो वर्षों में दो हजार करोड़ से भी ज्यादा एस.एम.एस. अलर्ट जारी किए जा चुके हैं ।

देश में स्थानीय स्तर पर आपदा तैयारियों और मोचन क्षमता को मजबूत करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए बहु-जोखिम आपदा संभावित 350 जिलों में आपदा के बचाव हेतु 1,00,000

सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए ?आपदा मित्र? योजना शुरू की गयी है और लगभग एक लाख स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित भी किया गया है ।

महोदय, एन.डी.आर.एफ. आपदा प्रबंधन/मोचन के विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़, चक्रवात, भूकम्प, भूस्खलन और सी.बी.आर.एन. के संबंध में सामुदायिक आपदा जागरुकता के विषय पर एक मॉक अभ्यास स्कीम को भी कार्यान्वित कर रहा है । एन.डी.आर.एफ. भारत के सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संवेदनशील स्कूलों में बच्चों को आपदा मोचन का प्रशिक्षण देने के लिए ?स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम? को भी क्रियान्वित कर रहा है ।

लोगों में जागरुकता पैदा करने के लिए एन.डी.एम.ए. और एन.डी.आर.एफ. द्वारा नियमित रूप से मॉक अभ्यास और सामुदायिक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ।

महोदय, गृह मंत्रालय दक्षिण-पश्चिम मानसून के शुरूआत से पहले इसकी तैयारी के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आयुक्तों का सम्मेलन भी आयोजित करता है । इस वर्ष यह सम्मेलन 11-12 जून, 2024 को आयोजित किया गया था । देश में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए 23.06.2024 को माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी केन्द्रीय एजेंसियों को राज्य सरकारों को उचित सहायता प्रदान करने के लिए निर्देश दिए गए ।

मानसून के पूर्व देश भर में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं और अभी 175 टीमें विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकारों की सहायता कर रही हैं । उच्चतम स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा स्थिति की निगरानी की जा रही है । गृह मंत्रालय के दोनों नियंत्रण कक्ष 24X7 स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और राज्य सरकारों को हर संभव मदद प्रदान की जा रही है ।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में सभी प्रकार की आपदाओं के जोख़िम को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है । अगर कोई आपदा आ जाती है तो उसमें बचाव एवं राहत कार्य किए जाते हैं । पहले से टैक्नोलॉजी का उपयोग और बाद में भी टैक्नोलॉजी का सहारा ले कर जो काम किए गए हैं, उसके कारण इन दस वर्षों में आपदा प्रबंधन भी सुदृढ़ हुआ है और जान-माल के नुकसान में भी काफी कमी हुई है । अगर एक उदाहरण दिया जाए, जब ओडिशा में सुपर साइक्लोन आया था, उसमें 10,000 लोगों की मौंत हुई थी । वहीं, अभी कुछ समय पहले गुजरात में जो साइक्लोन आया था, उसमें बाढ़ भी बड़ी मात्रा में होती है, क्योंकि बारिश अत्याधिक होती है, इसलिए मैं उसकी चर्चा करा रहा हूँ, बाकी तो उसके प्रकार हैं ही, वहां शून्य जान-माल की क्षति हुई थी । उसके पहले भी कई राज्यों ने इसका सहारा ले कर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर आपदाओं में जान-माल और संपत्ति के नुकान को काफी कम किया है ।

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, with great sorrow and disappointment, I would like to raise this issue of natural calamity, especially the huge landslide which has happened near Meppadi in Wayanad District of Kerala.

Yesterday early morning, the entire nation woke up hearing one of the saddest news we have ever heard. Since that time till now, the entire people of India, especially the people from Kerala, the Malayalis are weeping in front of TV channels. Horrifying scenes are witnessed of small children, their mothers and

elderly people. The dead bodies are floating in the rivers. Most of the dead bodies are not even in a position to be identified because they have been destroyed completely. Two entire villages have been devastated.

Sir, Wayanad is one of the natural scenic places in this country. God has given so much of beauty to that place, but yesterday a tragedy happened. This type of tragedy is not new for Wayanad. It has happened earlier also. Yesterday?s incident has actually shocked the entire humankind of this country.

Sir, we are very glad that the Government is ready to have a discussion on this issue.

Whenever this type of crisis happens, Government has to come forward for rescue measures. The Central and State Governments have to work together. In Kerala, there is a typical scenario. Last time when flood happened, the State Government and the Central Government along with people all over Kerala participated in the rescue mission. Basically, I am trying to say that poor fishermen rescued maximum people at that point of time. This time also, Wayanad is witnessing the same situation. The entire people of Kerala, especially people from Wayanad are cooperating with the rescue operations. There is the State Government, the Central Government, and all other agencies, especially, the NDRF team but still as per the reports, more than 150 people have lost their lives. Still more than 100 people are missing. We do not know the exact numbers. There is no answer to this. We can only request the Government to take maximum measures. It should take short-term action for rescue operations and give immediate relief to the deceased persons. It should take long-term measures to ensure that people get away from this type of tragedies.

Sir, the Government of India has already announced a compensation. Mostly there are plantation labourers there. All are poor people. The Government of India has to distinguish people not only in Wayanad. Entire Kerala is now having monsoons. Karnataka is having monsoons. The Government has to support the States financially to come over this situation. The hon. Home Minister said in the other House ? I am quoting from the media ? that there was a warning one week before 23rd itself about this landslide. I do not know. The State Government has to clarify it. The NDRF team is also there from 23rd onwards. Two things have to be verified. The early warning system has given warning on 23rd. On early morning of 30th this incident happened. What was the action taken by the State Government? What was the follow-up action taken by the Central Government? Has the evacuation process

been done by the State and whether the Central Government has to follow up for the evacuation? These two things are in the public domain only after the statement has been made by the Home Minister in the Rajya Sabha.

We do not want to politicise this issue in any way because this is the most painful disaster for this country. We are still praying. Those who are missing, their lives have to be saved. We are all praying for them. Entire Kerala is praying. The entire country is praying. Those who are working in the field, including the Army, the NDRF team, the State Government officials, they are all doing 24x7 work. But some strong measures have to be taken for assistance, rescue operations, and rehabilitation. There are modern technological methods to give early warning for this type of tragedies. I would like to know whether the Government is exploring them. There are world maps showing landslide and earthquake prone areas which give early warning to the people and the State officials.

Is the Government going to move forward technologically to get this system? I would like to know this from the hon. Minister, through you, Sir.

We cannot stop the natural calamities, but if the warning system is there, then several lives can be saved. There are many incidents where the warning system had given the warning and the evacuation happened in a successful manner and the lives were saved. I am not taking much time.

My request is that Kerala has faced the 2018-flood, 2019-flood, and landslides every year since the last five years. We are facing this type of big tragedies every year not only in Kerala but also in Karnataka, in the North Eastern States, in Bihar, and in Tamil Nadu. There should be some permanent system. I agree that there are systems to support this, but when this type of a situation is coming, then without ill-will, the Government of India has to come forward to support the States. We can politicize the issue once the rescue operations are over and whatever lives of the people have been saved. We can debate on it and move forward. But now, we should show the country that we are together to save our people. We are together to save the precious lives of our people. This is what I want to say. Jai Hind, Sir.

माननीय अध्यक्ष **:** मेरा सदस्यों से आग्रह है कि जैसे वेणुगोपाल जी ने सकारात्मक बात की, हम सकारात्मक बात करें । जैसे वेणुगोपाल जी ने विषय रखा और सब मिलकर, संसद इस पर गम्भीर चिंता कर रही है, ऐसा एक संदेश जाना चाहिए ।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, आपको कोई सप्लीमेंट्री पूछना है, तो पूछिए ।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Mr. Speaker Sir.

As rightly narrated by my learned friend, Shri K. C. Venugopal, the State of Kerala has never experienced such a disaster. The latest report goes to show that more than 160 people have lost their lives and more than 200 people are missing. Hundreds of people are in the hospitals and they are in the casualty wards.

We want to appreciate both the Central and the State Governments in having good coordination in the rescue and relief operations. Yes, we do admit the fact that our forces are doing a wonderful job in the rescue and relief operations in the area of disaster. But the basic point to be discussed, as rightly pointed out, is about the short-term measures. As far as we are concerned, the rescue and relief measures have to be given much importance.

Now, what is happening is that they are trying their level best to recover maximum dead bodies by removing all these concrete structures, by excavation, and it is very difficult because the climate is also not in good condition for having a positive rescue operation.

Firstly, I would like to mention about the series of incidents that are taking place in the same place and in the nearer places. I will just cite examples for it. On 8th August, 2019 in Malappuram District at Kavalappara, the same type of landslide took place and 11 bodies are yet to be recovered. On the same day, on 8th August, 2019, at Puthumala in Wayanad District, very near to this place, and at Vilangad in Kozhikode District, landslide took place and casualties have occurred.

My simple question to the hon. Home Minister is this. Is it in the notice of the Government that this area is an ecologically sensitive area and because of which the warning has to be given to take proper precautionary measures?

Secondly, regarding relief measures, I want to make an appeal to the hon. Minister. In the year 2004 when the tsunami took place, the then Speaker, Shri Somnath Chatterjee, with the request of the hon. MPs from the State concerned had given a direction by the then Speaker that Rs. 10 lakh of each MP?s MPLAD could be utilised for rehabilitation, relief and rescue measures in that particular disaster, and we all had given Rs. 10 lakh for rehabilitation of the tsunami-affected areas. So, today, I make an appeal to the hon. Speaker to discuss it with all the political parties and give a direction so that the rehabilitation of the area can be done with the help of the MP?s Local Area Development Fund. Almost Rs. 800 crore

will be collected for the rehabilitation of that area. These are the two points that I wanted to make.

Lastly, the reports on the ecologically sensitive areas as reported by the Madhav Gadgil Committee, subsequently by Kasturi Rangan Committee and by so many other Expert Committees have to be discussed in detail. Some formula and scientific mechanism have to be evolved to ensure that no such incident happens in future.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो विषय रखा है, मैं सभी राजनीतिक दलों से इस विषय पर चर्चा करूंगा ।

राहुल गांधी जी, आप बोलना चाहते हैं, सुरेश जी ने आपका नाम लिखाया है ।

SHRI RAHUL GANDHI (RAEBARELI): Sir, it is a huge tragedy in Wayanad and the military is doing a good job there. I think it is very important that we support the people of Wayanad and we give them as much support as is possible and I would request the Government to help the people of Wayanad in this difficult time. I think this is the second tragedy that has taken place. It first took place five years ago. It is quite clear that this area has ecological issues. So, this should be looked into. If whatever high-tech solution can be found, that would be good.

माननीय अध्यक्ष : विश्वेश्वर हेगड़े, आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं?

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसमें बोलने का मौका नहीं देते? एक मिनट, प्लीज बैठें ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आग्रह कर दूं, ध्यानाकर्षण, कॉल अटेंशन के अंतर्गत जो पहला सदस्य होता है, वह अपना विषय रखता है । बाकी सदस्य यदि आवश्यक हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरा भाषण का विषय इसमें नहीं होता है । इसलिए मैं आपको क्लियर कर दूं, प्रश्न हो तो पूछ लें ।

SHRI VISHWESHWAR HEGDE KAGERI (UTTARA KANNADA): Hon. Speaker, Sir thank you giving me the opportunity to speak on the Calling attention. Sir the landslide incident occurred in Wayanad, is the result of Global Warming and Climate Change. Similar incident of Landslide occurred at Shirooru in Ankola of my Uttara Kannada Parliamentary Constituency. Out of eight people died in the unfortunate incident only three bodies are yet to be traced out. Hon. Prime Minister, hon?ble Home Minister, Hon. Defence Minister responded immediately

and sent troops. The N D R F and the Sea Port Officers are conducting search operations from 16th July itself.

At this juncture, I would only say that we need developments, however it should be done based on scientific methods. Prior to carrying out development project, a proper scientific study should be conduct and based on the report development projects should be encourages. As the Western Ghats are ecologically very sensitive area, there is a need to do a proper study of its carrying capacity.

As the NHAI constructed a road near Shirura hill, which is being done in an unscientific method there is heavy rain caused the hill collapse. I would like to insist upon the Union government that in the coming days before taking up any development project, there must be a scientific study on it. I would also request the Union government to send another NDRF team to my Constituency to look into the landslide issue. And I urge upon the government to release funds under the Prime Ministers Natural Relief Funds to take relief activities and also for the compensation to the victims in the affected region.

माननीय अध्यक्ष**:** मैं फिर माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि इस विषय पर भाषण करने की आवश्यकता नहीं है । यह गंभीर विषय है ।

? (व्यवधान)

ADV. FRANCIS GEORGE (KOTTAYAM): Sir, I am not going to make any speech. The UN Inter-Governmental panel on Climate Change had reported that in the next 20 years, climate change will cause havoc and widespread natural calamities in Kerala. That report had come long back. I would like to ask from the hon. Minister what steps, especially for Kerala, have been taken by the Central Government to warn about these kinds of issues and also to mitigate, if something happens. what preventive measures have been taken by the Central Government?

There is one more thing which I would like to point out. In the Budget, five States have been included for disaster management under the Disaster Management Scheme for financial help. Kerala has been left out. Will Kerala be included in that also? I would like to ask these two questions.

SHRI K. RADHAKRISHNAN (ALATHUR): Sir, I am not going to elaborate.

Sir, what happened in Kerala is one of the major natural calamities in recent times. Earlier respected K.C. Venugopal and the hon. Opposition Leader had pointed out that what happened in Wayanad is a major calamity. Hundreds of people have lost

their lives, and hundreds of people are missing. Thousands of people have taken refugees in rescue shelters. Cutting across party differences, everyone is working together in relief activities. The Central Government has also extended all possible help and the Indian Navy, Army and Air Force are all engaged in relief work. The NDRF is also extending all help. The Kerala Government has also begun relief work on a war footing. Sir, I have just one point to add in this context. During the budget discussion also, I had mentioned that Kerala should be provided adequate funds and it receive other helps to counter such natural calamities in the future. The Wayanad disaster should be declared as a national disaster, and Kerala should get due financial help from the Centre. With these words, I bow my head in reverence to the memory of all those who have lost their lives. I conclude. Thank you.

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): Hon Speaker, Sir, thank you for allowing me to ask a few questions to the hon. Home Minister and the concerned authorities on a very sensitive matter that concerns not just Kerala, but other Southern States as well.

Sir, in the last five years, Kerala has repeatedly witnessed landslides which have taken the lives of hundreds of innocent people. In July 2022, the Ministry of Earth Sciences told the Lok Sabha that Kerala witnesses the maximum amount of landslides in the country, and up to 60 per cent of the landslides that have taken place in the country in the last five years, most of them are happening in Kerala. I want to ask this question. What are the Central Government and the State Government doing as a long-term measure to address this issue?

In just the last five years, more than 350 deaths have taken place in Kerala, just around the area of Wayanad and other regions where this has happened. Even this very year, in January, the IIT Delhi conducted a survey and said this district of Wayanad falls under the high to very high-risk category. In 2013 and 2011, two panel reports conducted a detailed assessment and thereafter they made recommendations on what the State Government has to do. But no illegal encroachments were removed ? (*Interruptions*) No action was taken to remove the construction activities taking place ? (*Interruptions*) No action was taken to reduce the mining that is taking place in these areas. ? (*Interruptions*) Sir, I also want to ask this to the hon. Minister. This is a very important issue. In 2020, the Kerala Disaster Management Authority advised relocating 4000 families from the landslide-prone areas in Wayanad. ? (*Interruptions*)

Till today, no action is taken. ... ? (*Interruptions*) I also want to ask you regarding a very, very important issue. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज कनक्लूड करें ।

? (व्यवधान)

15.46 hrs

At this stage, Sushri S. Jothimani, Shri Benny Behanan and some other hon.

Members came and stood on the floor near the Table.

SHRI TEJASVI SURYA: Speaker, Sir, I have a last question. इसके पीछे का कारण मैं बताना चाहता हूं । ? (व्यवधान) वर्ष 2021 में केरल विधान सभा में केरल के फॉरेस्ट मिनिस्टर ? जी ने यह एडमिट किया कि हम वहां से इल्लीगल एनक्रोचमेंट को इसलिए नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन्स से हमें प्रेशर है ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ओके ।

? (व्यवधान)

SHRI TEJASVI SURYA: Kerala?s Forest Minister admits in the Assembly that they are unable to remove the illegal encroachment because they have pressure from religious organisations. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : ओके, माननीय सदस्य प्लीज ।

? (व्यवधान)

श्री तेजस्वी सूर्या : अध्यक्ष जी, कांग्रेस के एमपी पीसी थॉमस जी ने इसी इश्यू को इससे पहले उठाया था और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? ? (व्यवधान) ?* ? (व्यवधान) आज सिर्फ वायनाड और वायनाड के आसपास के वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से एनक्रोचमेंट को ये नहीं हटा रहे हैं । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ओके, प्लीज माननीय सदस्य प्लीज ।

? (व्यवधान)

SHRI TEJASVI SURYA: ?

माननीय अध्यक्ष : श्री ई.टी, मोहम्मद बशीर, आप बोलिए ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री ई.टी, मोहम्मद बशीर ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही चार बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

? (व्यवधान)

15.48 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Sixteen of the Clock.

16.01 hrs

The Lok Sabha re-assembled at One Minute past Sixteen of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

माननीय अध्यक्ष **:** वेणुगोपाल जी, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं?

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): I was very thankful to the hon. Speaker and the hon. Minister of Parliamentary Affairs for allowing me to speak on the biggest tragedy, as a Calling Attention under Rule 197.

You know about Rule 197. The Rule states: ?A member may, with the previous permission of the Speaker, call the attention of a Minister to any matter of urgent public importance and the Minister may make a brief statement or ask for time to make a statement at a later hour or date?. In Calling Attention, basically, there is no scope for others to speak. But, Sir, you have allowed everybody to ask questions. From this side of the House, Adv. Francis George and Shri N. K. Premachandran asked questions. From that side of the House also, one Member from Karnataka asked a question. I would like to say that a very fruitful question was asked.

Hon. Speaker, Sir, I am again asking one thing. This is a big tragedy. We are still digging through the mud to search for the bodies. You think about those whose family members are missing. What is the atmosphere there? In the morning also, when this issue came up -- this is not the first time that this has happened -- the same Member said that the Karnataka Government did not do anything. Can I call it ?politics?? One incident happened in Wayanad. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** आप एक बात बताइए । आप सभी सदस्य उनको बोलने का मौका दीजिए । आप टोका-टोकी मत कीजिए । आप ऐसा मत कीजिए ।

? (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL: Hon. Speaker, Sir, I need to clarify it. ? (*Interruptions*) I am not politicising the issue. He has mentioned the name of an hon. Member of Parliament who has been a Member from Wayanad constituency for the last five years. Entire Kerala and the entire nation are proud of Shri Rahul Gandhi as a Member of Parliament from Wayanad constituency. The way in which the flood situation happened, he came there and he camped there. How much service has he done for the families there in Wayanad? I do not want to describe it. That is why, he has won more than 3,60,000 votes this time, which is more than the votes won by the Prime Minister, more than the majority of the Prime Minister.

माननीय अध्यक्ष **:** उन्होंने उनके विषय में नहीं कहा है ।

? (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, please allow me to speak. You were the Speaker in the previous Lok Sabha also. You know as to how many times Shri Rahul Gandhi intervened to speak about natural calamities in Wayanad. There are records. I am challenging that Member. There are records. How many letters had been given by him to the Chief Minister? How many letters had been given by him to the Government of India? ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** आपका विषय क्या है?

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** ओके ।

? (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, in this type of a situation, the entire country is expecting a fruitful discussion in the Parliament, which is the highest law-making body in the country. The Member tried to sabotage the entire discussion. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** आप चाहते क्या हैं ।

? (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, my point is that he has to apologise. ? (*Interruptions*) The Member has to apologise. ? (*Interruptions*) That should not be in the record. We are not going to politicise it. Shri Rahul Gandhi is appreciating the services of the military. We are appreciating the services.

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, एक मिनट के लिए रुक जाइए ।

? (व्यवधान)

डॉ**.** निशिकान्त दुबे **(**गोड्डा**) :** महोदय, मैं नियम 350 के तहत प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाना चाहता हूं । मुझे लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम और संविधान कंठस्थ है । मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है । नियम 350 यह कहता है कि इस हाउस में स्पीकर की अथॉरिटी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है, जिसको स्पीकर ने बोलने के लिए माइक दिया, वही बोलेगा । आपने तेजस्वी सूर्या को बोलने के लिए माइक दिया था, वे उसके आधार पर बोलें । यदि वेणुगोपाल जी उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो ये आपकी तौहीन है, इस रूल की तौहीन है । आप उनके ऊपर कार्रवाई करिए ।?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्यगण, सुबह शून्य काल के दौरान माननीय नेता प्रतिपक्ष ने आग्रह किया था और उन्होंने विषय रखा था । उसके बाद वेणुगोपाल जी और संसदीय कार्य मंत्री जी मुझसे मिले । उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस विषय पर कॉलिंग अटेंशन होना चाहिए । सरकार ने कहा कि यह गंभीर और चिंता का विषय है, इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए । सभी माननीय सदस्यों ने कहा, इसलिए मैंने कॉलिंग अटेंशन को अलाऊ किया ।

मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि आप जिस विषय को मेरे ध्यान में लाए हैं, उन्होंने किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर कोई आरोप नहीं लगाया है । जो ऐसा विषय है, जो इस सदन की मर्यादाओं और इस घटना की मर्यादा के अनुरूप नहीं है, मैंने आपसे चैंबर में भी कहा है, मैं इस सदन में भी कह रहा हूं, आपके साथ चर्चा करके, उन शब्दों को रिकॉर्ड में नहीं रखा जाएगा ।

श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर जी ।

? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई **(**जोरहाट**) :** महोदय, राष्ट्रीय आपदा पर इस प्रकार के राजनीतिकरण के लिए?(व्यवधान) वह माफी मांगने से छोटे नहीं हो जाएंगे ।?(व्यवधान) किस बात का अहंकार है?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** क्या आप गंभीर बात पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं? आप इस पर गंभीर नहीं हैं । क्या आप इस पर राजनीति करना चाहते हैं? ई. टी. मोहम्मद बशीर जी को बोलने दें ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आपकी कोई भी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है ।

? ? (*Interruptions*)

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM): Thank you Sir. I do not want to take much of your time. I would speak in brief only Sir. ?(*Interruptions*) I endorse the views expressed by Shri Venugopal and others.

Now, everybody is coherently doing the rescue work and for that all are cooperating ? whether it is the State Government or the Central Government. All are much worried about this because we have never witnessed this kind of calamity and it is playing havoc there. Nobody knows how many dead bodies are still under the soil. There is a newspaper report that one man cried from a collapsed house which was beneath the mud. In such a situation, we all will work together and work hard to restore normalcy and I will make a tribute also to those victims.

Towards the end, I would like to say only one thing. We must do introspection. India is proud to say that we are number one in the world as far as science and technology is concerned. What methods we have adopted for preparedness? When calamity was happening, preparedness to meet that calamity is the main thing. In this case, what happened? Who have committed this mistake? That has to be discussed in a peaceful manner. That is what, I am saying. If preparedness was there, this disaster could have been reduced. What I am suggesting is that we have to think loudly about that.

माननीय अध्यक्ष **:** ई. टी. मोहम्मद बशीर जी, प्लीज आप बैठ जाइए ।

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER: Who made the mistake? Who was responsible? Have we got early warning about this? All these things have to be discussed. That is for the betterment of the future. These are all the things which I wanted to say.

With these words, I conclude.

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, अगर इस पर डिबेट होने लगेगी कि जिम्मेदारी किसकी थी, किसको दी गई, इस विषय पर नहीं जाना चाहिए । हम उस पर मंथन और चर्चा कर लेंगे । फिर आप कहेंगे कि मंत्री जी ने ये कहा है, ठीक नहीं होगा । अगर आप ऐसा जवाब सुनना चाहते हैं, तो मंत्री जी वैसा जवाब देने के लिए भी तैयार हैं । अब मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे बोलें ।

? (व्यवधान)

गृह मंत्री**;** तथा सहकारिता मंत्री **(**श्री अमित शाह**) :** दादा, मुझे बोलने के लिए अलाऊ किया है । ?(व्यवधान)

प्रो**.** सौगत राय **(**दम दम**) :** महोदय, मैंने देखा कि तेजस्वी सूर्या ने क्या किया । अमित शाह जी के पास जाकर कहा कि राहुल गांधी ने पांच सालों तक क्या किया ।?(व्यवधान)

श्री अमित शाह **:** सौगत दा, प्लीज आप बैठ जाइए ।?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय गृह मंत्री जी ।

? (व्यवधान)

प्रो**.** सौगत राय **:** महोदय, ऐसा नहीं करना चाहिए ।?(व्यवधान)

श्री अमित शाह **:** दादा, मैंने उनको हिंदी में बोलने के लिए कहा है और कुछ नहीं कहा है ।

माननीय अध्यक्ष जी, कल भी और आज भी मेरे साथी नित्यानंद राय जी ने गृह विभाग की ओर से अधिकृत लिखित स्थिति के बारे में ब्यौरा इस सदन के पटल पर रखा है, परंतु आज डिस्कशन में कुछ मुद्दे खड़े हुए हैं । मेरे पास उनकी जो सूचनाएं हैं, इन्फॉर्मेशंस हैं, मैं उनको सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को साझा करने के लिए आपकी अनुमति से खड़ा हुआ हूं । सबसे पहले तो मैं इस दुखद आपदा में जिन-जिन लोगों ने अपने स्वजन गंवाए हैं, जो-जो लोग अभी लापता हैं, जबरदस्त ट्रॉमा में जी रहे हैं और जो इंजर्ड हुए हैं, उन सभी के प्रति मैं हृदय से अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपदा के इस समय में चाहे भारत सरकार हो, चाहे पॉलीटिकल पार्टीज़ हों, समय है केरल की सरकार, केरल की जनता और विशेषकर वायनाड के लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़े रहने और इसमें नरेंद्र मोदी सरकार कटिबद्ध है । मैं इस सदन के माध्यम से केरल की जनता और वायनाड की जनता से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की ओर से हर संभव मदद और हर संभव प्रयास बचाने के लिए, रिलीफ के लिए और रिहैबिलिटेशन के लिए किया जाएगा । जब वेणुगोपाल जी ने बात शुरू की, तब मेरा राज्य सभा में कोटेशन था, वह यहां रखा है । उन्होंने कहा कि मैंने राज्य सभा में ऐसा कहा है, फिर उन्होंने कहा कि अर्ली वॉर्निंग सिस्टम इस देश में होना चाहिए । मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं कि इस देश में वर्ष 2014 के बाद दुनिया के सबसे आधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किए गए हैं । दुनिया में बहुत कम देश हैं, जो सात दिन पहले आपदा का आकलन सार्वजनिक करते हैं, पूर्वानुमान सार्वजनिक करते हैं । भारत उन चंद चार-पांच देशों में है, जो सात दिन पहले पूर्वानुमान साझा करता है । कई सारे देश, ज्यादातर देश, मोर दैन 90 परसेंट देश तीन दिन पूर्व इस आकलन को साझा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम वर्ष 2023 से सात दिन पूर्व सारे आकलन देश की जनता और देश की राज्य सरकारों के लिए साझा करते हैं । साइक्लोन का अर्ली वार्निंग सिस्टम है, कोल्ड वेव का भी है, हीट वेव का भी है, बिजली का भी है, सुनामी का भी है, अर्थक्वेक की जितनी पॉसिबिलिटी है, उतना है, फ्लड्स का है, भूस्खलन का है । कई प्रकार के अर्ली वॉर्निंग सिस्टम 323 करोड़ रुपये और 2000 करोड रुपये, कुल मिलाकर 2300 करोड़ रुपये के खर्चे से देश की जनता की सुरक्षा के लिए इस्टैब्लिश किए गए हैं । बशीर साहब ने कहा कि क्या हुआ तो मान्यवर, जहां तक डिजास्टर मैनेजमेंट का सवाल है और लोगों को बचाने का सवाल है तो मैं कह सकता हूं कि वर्ष 2014 से पहले इस देश में आपदा का रिस्पॉन्स करने का एक ही तरीका था, एक ही डाइमेंशन था, वह बचाव था, मतलब रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन । आपदा आने के बाद सबको मदद करो और पुनर्वासन करो । नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, देश के प्रधान मंत्री बनने के बाद, इसमें बचाव का एंगल हुआ कि एडवांस में ही तैयारी ऐसी करो, जिससे किसी की जान न जाए और जीरो कैजुअलिटी अप्रोच हो ।

मान्यवर, पर्टिकुलर एक हिस्से के लिए हम हर बृहस्पतिवार को अगले पखवाड़े का पूर्वानुमान देते हैं, जो इतना सटीक नहीं होता है, मगर पूर्वानुमान देते हैं और 18 जुलाई को भी पूर्वानुमान दिया था कि केरल के पश्चिम तट के क्षेत्र में सामान्य से ज्यादा वर्षा होगी । फिर 25 जुलाई को उसको स्पेसिफिक करके कहा कि भारी और बहुत

भारी वर्षा होगी । इसके बाद 23 जुलाई को फिर कहा कि अति भारी वर्षा होगी, 20 एमएम से ज्यादा वर्षा होगी और इससे भी ज्यादा हो सकती है । माननीय सदस्यों द्वारा पूछा गया कि आपने एडवांस में क्या कदम उठाए । हमने 23 जुलाई को ही आठ एनडीआरएफ के दल वहां भेज दिए थे, चूंकि हमें मालूम था कि 30 तारीख के आस-पास भू-स्खलन होगा या बाढ़ आएगी या ज्यादा बारिश होगी तो उनकी जरूरत पड़ सकती है । हमारे संविधान की स्कीम के तहत डिजास्टर मेनेजमेंट में दो हिस्सों में जिम्मेदारी आती है । एक, दुनियाभर की टेक्नोलॉजी को भारत के लोगों के लिए यहां लाना, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, टेक्नोलॉजी से सृजित पूर्वानुमानों का विश्लेषण करना और विश्लेषण करके राज्य सरकारों और देश की जनता को एलर्ट करना । दूसरा, यह फेडरल स्ट्रक्चर है । राज्य की जिम्मेदारी है कि केन्द्र सरकार जो सूचनाएं भेजता है, उसके अनुरूप लोगों को आपदा आने से पहले ही वहां से हटा ले, उनको सुरक्षित जगह पर ले जाए । मान्यवर, कई राज्यों ने ऐसा सफलतापूर्वक किया है । एक जमाने में, वर्ष 2000 में केरल में साइक्लोन आया, जिसमें करीब-करीब दस हजार लोग मारे गए । परंतु, अभी-अभी केरल में जो साइक्लोन आया, उसमें सिर्फ एक जान गयी, क्योंकि सात दिन पहले सूचना दी गयी थी । जिसकी वजह से पूरा इवैक्यूएशन कर दिया गया था । इसलिए सिर्फ एक जान गयी थी । गुजरात में भी साइक्लोन आया और वहां भी सात दिन पहले सूचना पहुंच गयी थी । पूरा इवैक्यूएशन हो गया । मैं गर्व के साथ कहता हूं कि एक भी जान नहीं गयी और न ही कोई पशु मरा है । सात दिन बहुत बड़ा समय होता है और राज्य प्रशासन की जिम्मेदारी है लोगों को वहां से हटाने की । मैं किसी पर दोष नहीं मढ़ना चाहता हूं । ये प्रश्न खड़े कर रहे हैं और उनको लगता है कि इससे केन्द्र सरकार को घेर लेंगे । मैं अपनी तरफ से स्पष्टता कर रहा हूं । यहां पर कई रिपोर्टों में, हमारे बैंगलुरू के माननीय सदस्य के प्रति बहुत आक्रोश व्यक्त किया गया, लेकिन यह वास्तविकता है कि आईआईटी, दिल्ली का इसी साइड के लिए रिपोर्ट दिया गया है । यहां जितने अनिधिकृत लोग रहते हैं, उनको किसी भी स्कीम के तहत हटाया जाए । इसके बाद वर्ष 2020 में भी रिपोर्ट दी गयी कि इन लोगों को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि यहां बाढ़ और भू-स्खलन की ज्यादा संभावना है । मगर, नहीं हुआ । चार हजार परिवारों को हटाना चाहिए और कौन से चार हजार परिवारों को कौन सी जगह से हटाना चाहिए, यह भी इंगित किया गया है । मान्यवर, मुझे बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है कि यही दुर्भाग्यशाली लोगों हैं, जिनके लिए छ: साल पहले सूचना दी गयी कि इनको हटा लीजिए क्योंकि यह रिस्क जोन में हैं । लेकिन, उन्हें वहां से नहीं हटाया गया । मगर फिर भी जैसे ही सूचना मिली, एनडीआरएफ राज्य में जा सकती है, लेकिन एनडीआरएफ को लगाने का काम कलैक्टर के ऑर्डर से ही हो सकता है । जैसे ही कलैक्टर ने हमें सुबह चार बजे ग्रीन सिग्नल दिया, हम वहां पहुंचे, लोगों को बचाया । सेना पहुंची, इंडियन एयर फोर्स पहुंची, हेलिकॉप्टर पहुंचा, हमारी सीआईएसएफ की एक टुकड़ी वहां थी, जो वहां पहुंची । सेना ने तत्काल वहां एक कच्चा ब्रिज बनाया और वहां फंसे एक हजार लोगों को वहां से बाहर निकाला । सैंकड़ों लोगों को बचाने का काम हुआ है । लेकिन, ऐसे भी दुर्भाग्यशाली लोग थे, जिनको हम नहीं बचा पाए और इसका हम सबको नुकसान हुआ है । हम सबको दर्द भी है, दुख भी है । हम सबको नुकसान झेलना पड़ा है, उनके परिवारों को भी झेलना पड़ा है ।

मान्यवर, मेरा एक ही अनुरोध है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के मामले में सभी राज्य सरकारें, जितनी भी योजनाएं वर्ष 2014 के बाद बनी हैं, उसके संबंध में मैं एक बिल भी लेकर आने वाला हूँ, इसी सत्र में लेकर आने वाला हूँ, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा । कृपया आप इसका अभ्यास कीजिए । इसके अर्ली वॉर्निंग सिस्टम को, चूँकि वह कभी-कभार गलत भी हो सकता है, लेकिन फिर भी किसी को हटाने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन नहीं हटाया और बाढ़ आ गई और भूस्खलन हो गया तो लोग मारे जाते हैं । इसको गंभीरता से लेना चाहिए और स्फूर्ति के साथ इस काम को करना चाहिए ।

जहां तक स्फूर्ति का सवाल है तो भारत सरकार ने बचाव कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ी है । हमारा हर वर्टिकल जो बचाव के लिए बना है, वह हर वर्टिकल आज वहां पर मौजूद है । वे दिन-रात काम कर रहे हैं । प्रधान मंत्री

जी स्वयं कंट्रोल रूम से सीधे जानकारी ले रहे हैं । मेरा कार्यालय और मैं भी जानकारी ले रहा हूँ । नित्यानंद राय जी हर रोज चार घंटे कंट्रोल रूम में रहते हैं । मेरे एमओएस कंट्रोल रूम में खुद बैठ रहे हैं और उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं । मैं केरल की जनता को इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूँ कि रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे । भारत सरकार इस संकट की घड़ी में केरल सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ी है ।

____

16.21 hrs

-

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 343/18/24.